various international sectors from 0.1.01.90 onwards is indicated below:—

Period				Increase in Percentage
01 January 90	— 30 March 90	5.0	—	17.7
01 April 90	— 30 June 90	4.0	—	19.0
01 July 90	— 30 Sept. 90	4.54	—	27.54
01 October 90	— 31 Dec. 90	2.0	—	10.0
01 January 91	— 30 March 91	7.0	—	
01 April 91	— 30 June 91	3.0	—	20.0
01 October 91	— 31 Dec. 91	3.0	—	11.4
01 January 92	— 30 March 92	3.0	—	
01 April 92	— 30 June 92	5.0	—	15.0
01 July 92	— 30 Sept. 92	10.0	—	
01 October 92	— 31 Dec. 92	15.0	—	
01 January 93	— 30 March 93	8.5	—	
01 April 93	— 30 June 93	15.0	—	26.5
01 July 93	— 30 Sept. 93	15.0	—	
01 January 94	— 30 March 94	4.6	—	6.5
01 April 94	— 30 June 94	3.0	—	20.0
01 July 94	— 30 Sept. 94	3.0	—	20.0
01 April 95	— 30 June 95	0.90	—	9.86
01 July 95	— 30 Sept. 95	2.40	—	
01 October 95	— 31 Dec. 95	10.00	—	15.40
01 January 96	— 30 March 96	3.40	—	20.00
01 April 96	— 30 June 96	10.00	—	15.00

Fare increase effectecd by Indian Airlines is domestic sectors as under:—

Date	Increase in percentage
11.04.1990	15.7
26.09.1990	10.0
07.10.1991	20.0
02.10.1992	9.0
13.09.1993	15.0
25.07.1994	10.0—20.0
15.06.1995	Dollar fare fixed at 15% more than INR fare.
01.10.1995	12.0—23.0
01.01.1996	Dollar fare revised by 20%.

(b) and (c) Airlines are free to fix the fares on domestic sectors in their own commercial judgement keeping in veiw the input costs and the impact on traffic. As regards international fares, the increases are initally discussed and agreed by the airline at the Tariff Co-ordinating Conference of the International Air Transport Association (IATA) and implemented with the approval of the respective Governments. Such review of international fares is undertaken by IATA for different sectors from time to time.

इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र

3589. **डा० बाई० लक्ष्मी प्रसाद:** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इलैक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र बनाये गये हैं और इन पर सरकार के करोड़ों रुपये खर्च हो गये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन यंत्रों के माध्यम से मतदान शीघ्र होता है, गुप्त रहता है तथा इससे मतदान केन्द्रों पर किये जाने वाले कब्जे को रोकने में सहायता मिलती है;

(ग) मतदान प्रक्रिया में आरंभ में इन मशीनों का प्रयोग करने में क्या-क्या कठिनाइयां हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में राजनैतिक दलों के साथ बातचीत आरंभ की है अथवा करने का विचार रखती है, आरंभ की गई बातचीत का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) इस संबंध में राजनैतिक दलों के साथ-साथ अन्य गैर-सरकारी संगठनों की प्रतिक्रियाएं क्या-क्या हैं?

विधि कार्य, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी॰ खलप): (क) 1989 में भारत इलैक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बंगलौर और इलैक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ लिमिटेड, हैदराबाद से लगभग 75 करोड़ रुपए की लागत पर 75 हजार इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनें खरीदी गई थीं।

(ख) जी हां।

(ग) निर्वाचन आयोग के अनुसार, राजनैतिक दलों के कुछ दलों के कुछ नेताओं ने मशीनों के कार्यकरण के संबंध में गंभीर शंकाए और संदेह व्यक्त किए थे।

(घ) निर्वाचन आयोग ने इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के उपयोग के संबंध में अपनी राय देने के लिए मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से परामर्श किया था। राजनैतिक दलों की प्रतिक्रियाएं विवरण में दी गई हैं, जिसे सदन के पटल पर रख दिया गया है। (नीचे देखिए)

(ङ) गैर-सरकारी संगठनों से अभी तक परामर्श नहीं किया गया है।

विवरण

इलैक्ट्रानिक मशीनों के उपयोग के संबंध में विभिन्न राष्ट्रीय/राज्य के मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों की प्रतिक्रियाएं

	दल का नाम	जवाब
	राष्ट्रीय दल	
1.	भारतीय जनता पार्टी	कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।
2.	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी	आयोग के विनिश्चय की प्रशंसा की। चयन किए गए निर्वाचन क्षेत्रों में साक्षरता का उच्च स्तर होना चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग को निर्वाचन क्षेत्रों का अग्रिम रूप में पता लगाना चाहिए और उन्हें प्रकाशित करना चाहिए। मतदाताओं को इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों का उपयोग करने के संबंध में शिक्षित किया जाना चाहिए।
3.	भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)	इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों का उच्च साक्षरता वाले उच्चतर शहरी क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है। रीतियों और अन्य प्रबंधों को तैयार करने के लिए राजनैतिक दलों की बैठकें बुलाई जानी चाहिए।
4.	इण्डियन नेशनल कांग्रेस	यथा प्रस्तावित इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के उपयोग के लिए कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु चिन्हित निर्वाचन क्षेत्रों में इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के परिचालन को मतदाताओं की जानकारी के लिए ठीक प्रकार से प्रदर्शित किया जाए। अंतिम विनिश्चिय किए जाने से प्रदर्शित किया जाए। अंतिम विनिश्चिय किए जाने से पहले विधिक पहलूओं की भी जांच की जानी चाहिए।

दल का नाम	जवाब
5. जनता पार्टी	उन निर्वाचन क्षेत्रों में जिनमें साक्षरता की सापेक्षतः उच्चतर सीमा है, इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों के उपयोग का जोरदार समर्थन करती है। राज्य सरकारों को स्थानीय निकायों के निर्वाचनों के लिए इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों का उपयोग करने के लिए कहा जाना चाहिए। सभी निर्वाचनों में उच्च साक्षरता वाले शहरी क्षेत्रों में इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के उपयोग के लिए एक नियम होगा। इलैक्टॉनिक मतदान मशीनों के उपयोग से बूथों पर बलात् कब्जा करने को कठिन बनाएगा और परिणामों की शीघ्र घोषणा के सुनकर बनाएगा।
6. जनता दल	जनता दल बड़ी संख्या में शहरी क्षेत्रों में अशिक्षित मतदातओं को ध्यान में रखते हुए इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों के उपयोग के विरुद्द है।
7. समता पार्टी	कोई राय व्यक्त नहीं की थी, किन्तु आयोग के जवाब में निम्नलिखित प्रश्न उठाए: 1. स्वतंत्र पुनर्गणना की क्या संभावना है? विद्युत शक्ति के न होने, या इलैक्टॉनिक मतदान मशीन में गड़बड़ होने या दोष होने के कारण, मत का रजिस्ट्रीयकरण प्रभावित होगा और वैसा ही दोष पुर्नगणना में भी आएगा। 2. संसद में इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीने प्रायः दोषापूर्ण रही हैं, जिसके कारण ध्वनि मतदान और पर्चीं मतदान का सहारा लेना आवश्यक हुआ है। यदि मतदान केन्द्र पर ऐसी चूक होती है तो वैकल्पिक पद्धति क्या है? 3. निर्वाचकों के प्रशिक्षण के लिए क्या किया जा रहा है। केवल उच्च साक्षरता वाले क्षेत्रों में इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों का उपयोग करके, उनके पक्ष में दुर्भावना पैदा की जाती है। साक्षरता वाले क्षेत्रों में निरक्षरता वाले पाकिट हैं और इससे उनको नुकसान होगा। 4. क्या एक मार्ग दर्शी रूप में कोई परीक्षण किए गए हैं? क्या इस प्रकार के मतदान के लिए पहले किसी क्षेत्र का प्रयोग किया गया है। 5. बूथ के कर्मचारी वृन्दो को प्रशिक्षण देना आवश्यक है। 6. प्रत्येक इलैक्ट्रॉनिक मशीन में एक स्रोत कोड और सर्किट चक्र है। इससे पहले ही पक्षपात करने की संभावना है। ऐसी किसी संभावना को समाप्त करने के लिए पूर्णतया पारदर्शिता और विश्वास का वातावरण होना चाहिए। 7. सभी दलों के परामर्श से प्रक्रियाएं तैयार की जानी चाहिए। 8. यदि परीक्षण का क्षेत्र सीमित है तो, क्यों न स्थानीय मतदानों से ही शुरुआत की जाए?

दल का नाम		जवाब
		मान्यता प्राप्त राज्य दल
1.	आल इंडिया फारवर्ड ब्लाक	पूरे देश में इलैक्ट्रानिक मशीनों का सभी निर्वाचन क्षेत्रों में उपयोग किया जाए न कि चयन किए गए निर्वाचन क्षेत्रों में। तारीख 6-11-1995 को कलकत्ता में हुई राजनैतिक दल की बैठक में लिया गया यह हमारा निर्णय था।
2.	असम गण परिषद	केवल चयन किए गए निर्वाचन क्षेत्रों में इलैक्ट्रानिक मशीनों का उपयोग करना पक्षपातपूर्ण होगा। इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों का परिणाम ठीक नहीं हो सकते हैं। इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों का आने वाले साधारण निर्वाचनों में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
3.	मणिपुर पीपुल्स पार्टी	प्रस्ताव की अत्यधिक प्रशंसा की गई।
4.	आल इंडिया अन्ना द्रविड मुन्नेत्रा कड़गम	कुछ मजबूरियां व्यक्त की और कहा कि पार्टी तमिलनाडु में कुछ चयन किए गए शहरी निर्वाचन क्षेत्रों में भी इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों की शुरुआत करने के किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है।
5.	तेलगू देशम पार्टी (एन०टी० रामाराव)	प्रस्ताव का स्वागत किया।
6.	इंडियन कांग्रेस (सोशलिस्ट) (एस० डब्ल्यू० धाबे)	कमीशन का प्रस्ताव का इस प्रतिबंध के साथ स्वागत किया कि इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों का केवल उन क्षेत्रों में उपयोग किया जाएगा जहां पहचानपत्र जारी किए गए हैं।

Investment in blue chip companies by FII's

3590. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the new-item which appeared in the Economic Times dated 22nd August, 96, captioned "FIIT's growing stake in blue chips irks left";

(b) whether it is a fact that foreign investors are increasing their stake in blue chip companies;

(c) what is the reaction of Government to this trend: and

(d) steps proposed to safeguard national interest?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) Investment by Foreign Investors including Foreign Institutional Investors (FII's) through Global Depositary Receipt (GDR)/Foreign Currency Convertible Bond (FCCB) route, which is reckoned as part of Foreign Direct Investment (FDI) needs to conform to the norms applicable to FDI. Accordingly, a company is permitted to float Euro issue in the International Capital market for investment by foreign investors provided the following conditions are met:

(i) Eligibility condition of 3 years financial track record requirement.

(ii) Conform to FDI norms and accordingly obtain Foreign Investment Promotion Board (FIPB) approval where foreign equity after post Euro issue is likely to exceed 51% or where